

**Shri Jagjivan Ram:** That is exactly what I said. The arbitrator said that he will require some more time and naturally both the parties, that is, the Government and TELCO, agreed to it.

**Shri T. B. Vittal Rao:** May I know if there is a proposal under the consideration of the Railway Board to take over TELCO as recommended by the Public Accounts Committee some time ago?

**Mr. Speaker:** How does it arise out of this question? Whatever else happens in TELCO, apart from arbitration, is not covered.

**Shri Nagi Reddy:** When there would not be any arbitration at all

**Mr. Speaker:** Many things can happen

#### Re-Employment of Retrenched Employees

+

\*429. { Shri S. M. Banerjee  
Shri Tangamani }

Will the Minister of Railways be pleased to state.

(a) whether some of the workers retrenched on account of closure of some coach building factories in UP have been provided with alternative jobs in the Integral Coach Factory at Perambur, and

(b) if so, the number thereof?

**The Deputy Minister for Railways (Shri Shah Nawaz Khan):** (a) No Sir

(b) Does not arise

#### दुर्गम क्षेत्र समिति

\*430. **श्री भक्त बर्जान :** क्या साध तथा कृषि मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के तारारहित प्रश्न संख्या ११०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में साध सम्बन्धी आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के सुझाव देने के लिये

जिस दुर्गम क्षेत्र समिति की नियुक्ति की गई थी, उसने इस बीच अपने कार्य में क्या प्रगति की है ?

**कृषि उपजंत्री (श्री श्री० बें० कुञ्जप्पा):** तथा की टेबिल पर एक विवरण रखा दिया गया है ।

#### विवरण

२७ सितम्बर, १९५८ को दुर्गम क्षेत्र समिति की प्रस्तावली के उत्तर, आसाम सरकार को छोड़ कर, जिसको स्मरण-पत्र भेज दिया गया है, बाकी सभी राज्य सरकारों। प्रशासनों से अब प्राप्त हो चुके हैं ।

समिति ने सभ्यताओं का स्थल पर जाकर अध्ययन करने के लिये दौरा करने का कार्यक्रम फरवरी, १९५९ के दूसरे सप्ताह से बना लिया है ।

**श्री भक्त बर्जान :** इस विवरण से ज्ञात होता है कि इस समिति की स्थापना यद्यपि पांच महीने हुए ही चुकी थी, अभी तक केवल दफ्तरी काम ही हो पाया है और अब दौरा शुरू होने वाला है । मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी हालत में क्या थके जन तक अपनी रिपोर्ट दे सकेंगी ?

**श्री श्री० बें० कुञ्जप्पा :** इस समिति ने एक प्रस्ताव नी तारी गवर्नमेंट्स के पास भेजी थी और असम की सरकार को छोड़ कर सभी राज्य सरकारों ने अपने उत्तर भेज दिये हैं । असम सरकार को भी स्मरण-पत्र भेजा गया है और कहा गया है कि वह भी जल्दी में जल्दी अपना उत्तर भेजे । समिति ने दूर करने का भी इतिहास कर लिया है ।

**श्री भक्त बर्जान :** जैसा कि समिति के टर्म्स ऑफ रेफरेंस से स्पष्ट होता है इस कमेटी ने यह पूछा गया है कि क्या इन इलाकों को आद्योत्पादन के मामले में आत्म-निर्भर बनाया जा सकता है या नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि ये इलाके चाहे कितना भी प्रबन्ध क्यों